कारोबार में सुगमता को बढ़ावे के लिए नियमों में ढील देने पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में प्रदेश में कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। भारत सरकार की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नियमों में ढील देने का सुझाव दिया है।

मुख्य सचिव के कार्यालय में हुई बैठक में केंद्र सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की सचिव मीता राजीवलोचन ने इस संबंध में कई सुझाव दिए। कहा कि अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), उद्योगों की स्थापना तथा फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), औद्योगिक क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता और उद्योगों के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है। उन्होंने अनुपालन में कमी और डीरेगुलेशन पर पांच महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष फोकस करने का सुझाव दिया। इनमें भूमि, भवन-निर्माण, श्रम, उपयोगिताएं, अनुमति व प्राथमिकताएं शामिल हैं।

मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सोमवार को अनुपालन में कमी और डीरेगुलेशन पर आयोजित बैठक को संबोधित करते ● सूचना विभाग

उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी की जा सकती है। कार्यबल में महिलाओं की पांच प्रतिशत की वृद्धि भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दे सकती है।

वहीं इन्वेस्ट यूपी के सभागार में टास्क फोर्स के साथ हुई बैठक में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा कि उत्तर प्रदेश कारोबार में सुगमता में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। निवेश मित्र तथा निवेश सारथी जैसे आनलाइन प्लेटफार्म से इसे बढ़ावा मिला है।

एक अप्रैल से राज्य कर्मियों को पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

राब्यू, जागरण● लखनऊ : सरकार ने राज्य कर्मियों को एक अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से भरने के निर्देश दिए हैं। इसमें सर्विस बुक, वार्षिक संपत्ति विवरण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन, वेतन आहरण, कार्य मुक्ति व कार्य ग्रहण करने जैसे काम प्रमुख हैं। अवकाश के लिए भी आनलाइन पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि इस वर्ष 17 जनवरी को जारी शासनादेश के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर सभी को अनिवार्य रूप से अपना विवरण आनलाइन भरना था, इसके बावजूद इसका पालन अनिवार्य रूप से नहीं किया जा रहा है।

कारोबार करने में सुगमता पर मंथन

लखनऊ, विशेष संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स ने यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ बैठक कर राज्य में कारोबार करने में सुगमता के मुद्दे पर मंथन किया। केंद्र सरकार के युवा मामलों की सचिव मीता राजीव लोचन ने कहा कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सुधार के लिए नियमों में ढील देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की कार्यबल भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें 5% की मामूली वृद्धि भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान दे सकती है। टास्क फोर्स ने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश के साथ अलग से बैठक कर ईज आफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा की।

भारत सरकार में सचिव मीता राजीव लोचन ने इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक की।

- महिला भागीदारी में 5% की वृद्धि से 26,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान
- बैठक कर ईज आफ डूइंग बिजनेस पर चर्चा की

यूपी लगातार अचीवर स्टेट बना : अभिषेक प्रकाश

बैठक में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में एक अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। निवेश मित्र तथा निवेश सारथी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। यूपी लगातार तीसरे वर्ष लॉजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स) रैंकिंग में 'अचीवर स्टेट' बना।